have been formulating system improvement schemes to strengthen and improve their transmission and distribution systems. 19898 persons were prosecuted and punished with fine or imprisonment or both, during the years 1984-85, 1985-86 and 1986-87 for pilferage of energy. Prosecutions for the theft of energy were launched against 2023 persons during the year 1987-88. System Improvement Schemes in respect of 29 major urban areas have been prepared and these are under various stages of clearances/implementation.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन कार्यरत बायोगैस विकास संयंत्र

2044. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन कार्यरत बायोगैस विकास संयंत्र बम्बई में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र की स्थापना बायोगैस के क्षेत्र में नए अनुसंधान कार्य करने के लिये की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई थी और अनुसंधान के क्षेत्र में इस संस्थान की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संस्थान पर किये जाने वाले खर्च का कुल वार्षिक बजट कितना है?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) जी नहीं। केन्वीन्आईन्सीन् द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रीय नवीकरणीय उर्जा संस्थान (नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिन्युएबल एनर्जी) नासिक में है।

(ख) यह केन्द्र न केवल बायो-गैस अनुसंधान के लिए बल्कि एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए भी स्थापित किया गया था।

(ग) यह केन्द्र जुलाई, 1989 में स्थापित किया गया था। चूंकि यह केन्द्र हाल ही में स्थापित किया गया था इसलिए अनुसंधान कार्य के परिणाम यथा समय पर उपलब्ध होंगे।

(घ) इस अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान पर 1989-90 के दौरान केन्वीन्आईन्सीन् का व्यय 10.54 लाख रुन् के लगभग था।

Submision of Break-up of Non-Scheduled Formulations

2045. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY:
SHRIMATI MANORAMA PANDEY:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is mandatory for every drug company to provide break-up of non-scheduled formulations to his Ministry under provision 11 of DPCO, 1987;

(b) if so, the names of the non-scheduled finished medicines where companies have intimated MAPE more than 125%;

(c) what was the material cost, ex-factory cost and MAPE indicated for each formulation;

(d) whether it is a fact that as per DPCO, 1987 every drug company has to submit Form 6 yearly;

(e) if so, the names of the companies and years for which Form 6 was submitted by each;

(f) what are the names of non-scheduled bulk drugs whose sales turn over per year has been reported more than rupees fifty lakhs; and

(g) what are the reasons for inclusion of each under non-schedule list?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Such formulations being thousands in number, the time and labour involved in the exercise will not be commensurate with the results likely to be achieved.

(d) Yes, Sir.

(e) and (f) The information has been given in the Statement (See below).

(g) The list of price controlled drugs was finalised on the basis of the recommendations of the Kelkar Committee.